इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रतिवर्ष 40/रुपये

(आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 2 अंक सं. : 07 परवरी 2010

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं---------- 1
अर्थव्यवस्था---------- 3
जिंस बाज़ार----------3
बीमा ---------- 4
नयी नियुक्तियां----------4
उत्पाद एवं गंठजोड़ ---------- 4
विनियामक के कथनं---------- 5
विशिष्ट घटनाएं----------6
बैंकों के तीसरी तिमाही के परिणाम----------7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---------- 7
शब्दावली ---------- 7
संस्थान समाचार----------8
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

मौद्रिक नीति की समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने तीसरी तिमाही की मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) दो चरणों में 75 आधार अंक (bps) बढ़ा कर 5.75 % कर दिया गया है। यह प्रणाली में मौजूद 36,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त चलनिधि अवशोषित करेगा।

- 4.75 % की पुन: खरीद (Repo) दर अथवा 3.25 % की प्रत्यावर्ती (reverse) पुन: खरीद दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

- चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अनुमान बढ़ा कर 7.5 % कर दिया गया है।

- मार्च, 2010 के अंत के लिए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से सम्बन्धित स्फीति का अनुमान बढ़ा कर 8.5 % कर दिया गया है।

- स्फीतिकारक प्रत्याशाओं को नियंत्रित रखने पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान।

एटीएम अंधों के अनुकूल बनेंगे

स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएमों) के नकदी आहरण हेतु अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप बैंक यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकलांग ग्राहकों की भी इन मशीनों तक पहुंच हो।

प्रारंभिक तौर पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के लगभग 7,000 एटीएमों को अंधे व्यक्तियों द्वारा उपयोग हेतु तैयार किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के वैकल्पिक माध्यमों के महा प्रबन्धक श्री अमिताभ कुमार ने बताया कि बैंक ने एटीएमों की एक प्रायोगिक परियोजना का काम पूरा कर लिया है, जिसमें दृष्टिहीन लोगों के लिए इंटरनेट बैंकिंग के एक सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की गई है।

पांच वर्षों में बैंक स्टाफ की उत्पादकता दोगुनी हो गई

पिछले कुछेक वर्षों में भारतीय बैंकों के कर्मचारी अधिक उत्पादक हो गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकों के एक पार्श्व-चित्र (Profile) 2008-09 के अनुसार वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक की पांच वर्षों की अवधि में भारतीय बैंकों का प्रति कर्मचारी औसत कारबार और लाभ दोगुने से अधिक हो गया है। यह बढ़ोत्तरी कारबार विकास के जनशक्ति से आगे निकल जाने के कारण हुई है। भारतीय बैंकों ने वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि में कुल 135 % की कारबार (अग्रिम और जमा) वृद्धि दर्ज की है, जबकि उनके कर्मचारियों की संख्या में केवल 10 % की ही वृद्धि दर्ज हुई है। उनके शाखा नेटवर्क में 21 % की बढ़ोत्तरी हुई है।

200,000 भर्तियों से बैंक आपके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सेवानिवृत्त अध्यापकों, किराना दुकान मालिकों और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के प्रचालकों को कारबार संपर्कियों (BCs) के रूप में नियुक्त किए जाने की अनुमति प्रदान कर दिए जाने के फलस्वरूप बैंक वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित पहलकदमियों को आगे बढ़ाने के लिए आगामी कुछेक वर्षों में 200,000 से अधिक व्यक्तियों को रखने की तैयारी कर रहे हैं। जहां देश के सबसे बड़े उधारदाता भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कम से कम 40,000 लोगों को नियुक्त किए जाने की आशा की जाती है, वहीं पंजाब नैशनल बैंक (PNB) 75.000 अतिरिक्त लोगों को भर्ती करने की तैयारी में है, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अगले 2-3 वर्षों में 50,000 लोगों को रखना चाहता है। इन कारबार संपर्कियों को जमाराशियां संग्रहीत करने, खाता धारकों की नकदी आहरित करने में सहायता करने तथा जीवन बीमा जैसे अन्य उत्पादों को बेचने के काम में लगाया जाएगा। कारबार संपर्कियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले हस्त-धारित उपकरणों का सर्वाधिक उपयोग देश के एक कोने से दूसरे कोने तक निधियां विप्रेषित करने में किया जाएगा।

ऋण, जमा वृद्धि के क्षेत्र में सरकारी बैंकों ने निजी क्षेत्र के महारथियों को पीछे छोड़ा

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने जमाराशियों और ऋणों में अपने बाज़ार अंश को बढ़ाने का क्रम जारी रखा, क्योंकि विदेशी और निजी बैंकों के कारबार में सितम्बर, 2009 में समाप्त तिमाही के दौरान पुन: कमी परिलक्षित हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक समूह के समावेश वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इसके ऊपर यथावर्णित अवधि के दौरान अपने-

अपने बाज़ार अंशों में बढ़ोत्तरी दर्ज की है। जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों ने जमाराशियों में उनके अंश में 48.6 % के पिछले तुलनीय आंकड़ों के मुकाबले 50.5 % की वृद्धि दर्ज की, वहीं स्टेट बैंक समूह ने अपना बाज़ार अंश 23.8 % (23.2 %) बढ़ाया। इस बीच निजी क्षेत्र के और विदेशी बैंकों को जमाराशियों के उनके अपने अंशों में क्रमश: 17.1 % (19.4 %) और 5.6 % (5.8 %) की कमी का सामना करना पड़ा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुनर्वित्तीयन फर्मों के प्रावधान मानदंडों को स्पष्ट किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि अस्थिर प्रावधान (floating provision) केवल असाधारण परिस्थितियों में विशिष्ट प्रावधान करने हेतु आकस्मिकताओं के लिए होते हैं, सावधि उधारदात्री और पुनर्वित्तीयन कम्पनियां विशिष्ट प्रावधानीकरण के स्थान पर अस्थिर प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकतीं। ये सावधि उधारदात्री कम्पनियां केवल असाधारण परिस्थितियों में ही कम्पनी के निदेशक बोर्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से विशिष्ट प्रावधान करने के लिए अस्थिर प्रावधानों को प्रतिलेखित (write back) कर सकती हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग कार्यान्वित करने की आपाधापी

सरकार द्वारा स्वाधिकृत बैंक जून 2010 तक एक ऐसे केन्द्रीकृत सॉफ्टवेयर की व्यवस्था करने की जल्दबाज़ी में हैं, जो ग्राहकों को कई प्रकार के चैनलों के माध्यम से सर्वत्र उनके खातों तक पहुंच रखने में समर्थ बनाएगा। सरकार की अनूठी पहचान परियोजना, जिसमें बैंकों से उप-रजिस्ट्रार के रूप में काम करना अपेक्षित है, को सुगम बनाने के लिए नेटवर्क में शामिल किए जाने की आवश्यकता उनके द्वारा बरती जा रही जल्दबाज़ी का एक और कारण है।

यूको बैंक द्वारा समावेशन की दिशा में एक नया कदम

वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के एक उपाय के रूप में यूको बैंक एक चल शाखा सेवा की योजना बना रहा है। यह पहलकदमी बैंक को चल वाहनों पर ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों तक पहुंचाएगी। मूल शाखा के विस्तार काउंटर के रूप में काम करने वाली ये चल शाखाएं लगभग 50, 000 लोगों की आवश्यकताएं पूरी करेंगी। जहां बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) जैसे कुछेक अन्य बैंकों ने चल एटीएमों की व्यवस्था कर रखी है, वहीं यूको बैंक की चल शाखा उन सभी प्रकार की सेवाएं (एटीएमों सहित) उपलब्ध कराएगी, जो आम तौर पर कोई शाखा प्रदान करती है। यूको बैंक इस सेवा की शुरूआत उत्तर प्रदेश में अमेठी से करेगा और उसके बाद एक वर्ष के भीतर इस प्रकार की 100 चल शाखाएं पूरे देश में परिचालित करेगा।

श्वेत पत्र (white paper) में सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों के विलयन की सिफ़ारिश

वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के समेकन के सम्बन्ध में नियुक्त विश्व-स्तरीय परामर्शदाताओं मैकिन्से एण्ड कम्पनी तथा अर्न्स्ट एवं यंग (E & Y) द्वारा तैयार किए गए एक श्वेत पत्र में चार बैंकों के दो अलग-अलग संस्थाओं के रूप में समामेलन की सिफ़ारिश की गई है। वित्त मंत्रालय ने इन फर्मों की नियुक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उन संभाव्य अभ्यर्थियों को सुझाने के लिए की थी जिन्हें अपेक्षाकृत बड़े और सुदृढ़ बैंकों का गठन करने हेतु समामेलित किया जा सकता है। परामर्शदाताओं ने सांस्कृतिक सहक्रियाओं, भौगोलिक उपस्थिति तथा अन्य समानताओं के अलावा लाभप्रदता एवं सम्बन्धित बाज़ार अंश को ध्यान में रखते हुए चार समुच्चयों का सुझाव दिया है। ऐसा माना जाता है कि सभी समुच्चयों का बाज़ार अंश 7% और 8 % के बीच में था।

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के निकट

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (SBM), जो कारबार संपर्कियों की नियुक्ति के माध्यम से वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, द्वारा 2,000 लोगों से अधिक की आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक कारबार संपर्की की नियुक्ति के माध्यम से वित्तीय समावेशन का अपना लक्ष्य मार्च, 2010 तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के प्रबन्ध निदेशक श्री दिलीप मविनकुर्वे ने कहा, " हम वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत नो- फ्रिल्स खाता मॉडल के अधीन 3 लाख लोगों को पहले ही शामिल कर चुके हैं तथा हमारे द्वारा एक जिला- एक बैंक मॉडल का लक्ष्य भी शीघ्र ही प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक का संयोजकता अभियान बैंकों को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विस्तार हेतु प्रेरित करेगा

बैंक भारत के दूरवर्ती उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में और अधिक शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग सेवाओं की पैठ बढ़ाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए प्रत्येक शाखा के लिए प्रति माह 12,000 रुपये के वी-सैट पट्टा किराये की प्रतिपूर्ति करने पर सिद्धान्ततः सहमत हो गया है। वी-सैट (वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल) की सहायता से शाखाएं उपग्रह के माध्यम से अपने बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) प्लेटफार्म से बेतार (wireless) संयोजकता (connectivity) स्थापित कर सकती हैं तथा ग्रामीण जनसंख्या के लिए बैंकिंग लेनदेन को सुगम बना सकती हैं।

भारतीय बैंक संघ ने आधारभूत सुविधा क्षेत्र को उधार देने हेतु सरल मानदंडों की मांग की

भारतीय बैंक संघ (IBA) ने आधारभूत सुविधा क्षेत्र, जिसके लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 514 बिलियन डालर के निधीयन की परिकल्पना की गई है, को ऋण प्रदान करने के लिए विनियामक रियायतों की मांग की है। बैंकों ने उक्त योजना में यथापरिकल्पित 43 % का अपेक्षित निधीयन करने हेतु वित्तीय रियायतों की मांग की है। भारतीय बैंक संघ ने 4 लाख रुपये तक के शैक्षणिक ऋणों को सुरक्षित करने के लिए ऋण गारंटी निधि की भी वकालत की है, क्योंकि वर्तमान मानदंड चूकों की संभाव्यता के बावजूद प्रतिभूति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देते। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष श्री एम.वी. नायर ने कहा है कि बैंकों के

लिए आधारभूत सुविधा निधीयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आवश्यक होगा। सकल बैंक ऋणों में आधारभूत सुविधा में बैंक वित्त का अंश वर्ष 2001 के केवल 1.8 % से बढ़ कर वर्ष 2009 में 10.2 % हो गया है तथा इसके और भी अधिक बढ़ने की आशा है।

अनियमित पुनरुत्थान भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यसूची में शीर्ष स्थान पर

यद्यपि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) नवम्बर में 11.7 % बढ़ा, तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक को यह पुनरुत्थान अब भी कम लगता है तथा उसका कहना है कि अनियमित पुनरुत्थान उसके चिंतन को निरंतर प्रभावित करता रहेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा, "वृद्धि के स्वरूप में अब भी असंतुलन मौजूद है। पुनरुत्थान हो रहा है, किन्तु वह कुछ हद तक अनियमित है।" औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में नवम्बर, 2009 में अक्तूबर, 2009 के 10.3 % तथा एक वर्ष पहले (नवम्बर, 2008) के 2.5 % की तुलना में 11.7 % की वृद्धि दर्ज हुई । भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह दावा किया है कि वह इस तथ्य से पूरी तरह अवगत है कि मुद्रास्फीति, जो मुख्यत: खाद्य पदार्थों की कीमतों के कारण हुई है, एक सामान्य मुद्रास्फीति का रूप ले सकती है। डॉ. गोकर्ण ने कहा, "हम पुनरुत्थान के क्रम को जारी रखना चाहते हैं और उसमें हर सभव तरीके से उसे मुद्रास्फीति की अवांछित दर के रूप में फैलने का अवसर दिए बिना सहायता करेंगे।"

अर्थव्यवस्था

दूसरी तिमाही में चालू खाते का घाटा बढ़ कर 12.6 बिलियन

व्यापार घाटे के अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद, चालू खाते का घाटा, जो वर्ष 2009-10 की दूसरी तिमाही में 12.6 बिलियन डालर था, मुख्यत: कमतर निवल दृश्य अधिशेष के कारण लगभग पिछले वर्ष के स्तर जितना ही रहा। हालांकि, अदृश्य अधिशेष के निजी अंतरणों और सॉफ्टवेयर निर्यात से प्रेरित होने की प्रवृत्ति जारी रही। वाणिज्यिक वस्तुओं का व्यापार घाटा मुख्यत: तेल के आयात में कमी के कारण अप्रैल - सितम्बर 2009 के दौरान एक वर्ष पहले की अवधि के 64.4 बिलियन डालर के मुकाबले 58.2 बिलियन डालर के रूप में कम रहा। वर्ष 2009-10 की दूसरी तिमाही के दौरान भारत में हुए सकल पूंजी अन्तर्वाह की रकम मुख्यत: 55.8 बिलियन डालर के अपेक्षाकृत अधिक विदेशी निवेश अन्तर्वाह के कारण वर्ष 2008-09 की दूसरी तिमाही में 90 बिलियन डालर की तुलना में 98.1 बिलियन डालर रही। वर्ष 2009-10 की दूसरी तिमाही में निवल पूंजी प्रवाह भी मुख्यत: भारी निवल विदेशी निवेश अन्तर्वाहों और उक्त तिमाही के दौरान अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किए गए विशेष आहरण अधिकार आबंटनों के कारण वित्तीय वर्ष 2008-09 की इसी अवधि के 7.1 बिलियन डालर के मुकाबले 23.6 बिलियन डालर के रूप में पर्याप्त रूप से अधिक रहे। महत्वपूर्ण मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर के मूल्यह्रास का निरूपण करने वाले मूल्यांकन अभिलाभ की रकम अप्रैल - सितम्बर, 2008 के दौरान 19, 760 मिलियन डालर थी। तदनुसार,

अप्रै ल - सितम्बर, 2009 के दौरान मूल्यांकन अभिलाभ का अंश विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि में हुई कुल वृद्धि का 67.5 % था।

जिंस बाज़ार

जिंस बाज़ार वर्ष 1973 के बाद से सर्वाधिक मज़बूत स्थिति में

एक दशक में तेल के सर्वाधिक बड़े वार्षिक अभिलाभ तथा तांबे और चीनी की कीमतों में दोगुनी से भी अधिक की बढ़ोत्तरी से उछाल पा कर जिंस बाज़ार वर्ष 1973 के बाद सर्वाधिक मज़बूत स्थिति में आ गया। रूटर्स जेफरी का सीआरबी सूचकांक वर्ष 2009 में 24 % की वृद्धि के साथ शिखर पर पहुंच गया। सोने में इतने ही वर्षों में नौवीं बार वृद्धि आसन्न थी। सफेद चीनी में रिकार्ड बढ़ोत्तरी हुई तथा कोकोवा में चौथी वार्षिक वृद्धि सन्निकट थी। किन्तु जो रणनीतियां वर्ष 2009 में काम आईं, वे आगामी वर्षों में असफल हो सकती हैं, क्योंकि बाज़ार वर्ष 2008 में आरंभ हुई वित्तीय मंदी की पृष्ठभूमि में शेष रह गई सौदेबाजी से शुरूआत करने के स्थान पर नयी शुरूआत कर रहा है। वर्ष 2009 वास्तविक रूप से मूल्य साध्य रहा; यह मूल्य की दृष्टि से अत्यधिक खरीदी वाला वर्ष था, जो बाज़ार में सस्तेपन से लाभ उठाने का अवसर था। एएनजेड में पण्य अनुसंधान के प्रधान श्री मार्क परवान ने कहा, "वर्ष 2010 काफी हद तक स्थूलताओं से प्रेरित होगा, अधिक विश्वासवादी रूप से प्रेरित होगा। आपको डालर से होने वाला प्रभाव इतना अधिक देखने में नहीं आएगा। यह आपूर्ति और मांग से और अधिक गहन रूप से जुड़ा होगा।"

जिंस बाज़ारों ने सूर्य प्रकाश की अनुपल्बधता (sun outage) से बचने का तरीका खोज निकाला

राष्ट्रीय जिंस व्युत्पन्नी बाज़ार द्वारा अपने सदस्यों से 20 फरवरी से वी-सैट के बजाय किसी वैकल्पिक मोड के माध्यम से कनेक्ट होने के लिए कहे जाने के परिणामस्वरूप जिंस बाज़ारों में सूर्य प्रकाश की अनुपलब्धता (sun outage) के दौरान लेन-देन का निलंबन शीघ्र ही इतिहास बन जाएगा। बहु-जिंस बाज़ार पिछले पांच वर्षों से भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) द्वारा संयुक्त रूप से उपलब्ध कराई गई उन्नत डाटा नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सूर्य प्रकाश की अनुपलब्धता (sun outage) के कारण समस्या का सामना करता रहा है। सूर्य प्रकाश की अनुपलब्धता (sun outage) की घटना उस समय होती है, जब कोई उपग्रह और पृथ्वी पूर्ण संरेखण की स्थिति में होते हैं। उक्त बाज़ार ने दलालों को सूर्य प्रकाश की अनुपलब्धता (sun outage) की घटना के दौरान, जो सामान्यतया एक वर्ष में दो बार -फरवरी - मार्च और सितम्बर - अक्तूबर में होती है, 20 फरवरी से पहले वी-सैट के बजाय वैकल्पिक मोडों से कनेक्ट हो जाने की सलाह दी है।

बीमा

सामान्य बीमाकर्ता मोटर बीमा ब्यूरो की स्थापना करेंगे

सामान्य बीमा परिषद सामान्य बीमाकर्ताओं के साथ मिल कर एक मोटर बीमा ब्यूरो (MIB) स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। यह उन वाहनों का पता लगाएगी, जो उनके अन्य पक्ष बीमों, जो कानून के तहत अनिवार्य है और जिसमें किसी दुर्घटना के दौरान वाहन के मालिकों और उसके यात्रियों के अलावा दुर्घटनाग्रस्त लोगों की सुरक्षा भी शामिल होती है, का नवीकरण नहीं कराते। इन आंकड़ों को सभी बीमाकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे वाहन के मालिकों से संपर्क कर सकें और उन्हें सुरक्षित करा सकें। उक्त डाटाबेस को स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे भी समुचित उपाय कर सकें। भारत में कुल 12 करोड़ वाहनों में से लगभग 3 करोड़ (संख्या की दृष्टि से प्राय: एक-चौथाई) वाहन गैर-बीमित ही चलाए जाते हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम ने 51 % नयी प्रीमियम आय का लक्ष्य प्राप्त किया

भारत के सबसे बड़े जीवन बीमाकर्ता, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को नये कारबार प्रीमियम (NBP) आय में चालू वित्तीय वर्ष के 48,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को प्राप्त कर लिए जाने की आशा है। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री डी.के. मेहरोत्रा द्वारा यथा-पुष्ट समाचार के अनुसार निगम ने दिसम्बर, 2009 के अंत तक (25, 000 करोड़ रुपये एकत्रित करते हुए) उसके लक्ष्य का 51 % पहले ही प्राप्त कर लिया है। जीवन बीमा कारबार में भारतीय जीवन बीमा निगम का बाज़ार अंश लगभग 65-66 % है तथा वह उसे बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करेगा। श्री मेहरोत्रा इस बात की पुष्टि करते हैं कि "हम वर्तमान में अपने एजेन्टों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 60-70 करोड़ रुपये का निवेश करते हैं तथा इस बजट को बढ़ाने पर विचार करेंगे।" इस समय पूरे देश में स्थित निगम के पास लगभग 14 लाख एजेन्ट हैं तथा इसमें 20% की और बढ़ोत्तरी होगी।

अंकीकरण जीवन बीमा निगम के पॉलिसी धारकों को परिपक्वता मूल्य आसानी से प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा

लागू की जा रही अंकीकरण (Digitisation) प्रथा के फलस्वरूप जीवन बीमा निगम के पॉलिसी धारक शीघ्र ही उनकी सुविधा के अनुसार शाखा से ठीक उसी प्रकार अपने परिपक्वता मूल्य, अभ्यर्पण मूल्य और ऋण मूल्य आहरित करने में समर्थ होंगे, जिस प्रकार वे अपने प्रीमियमों का भुगतान इस बात को ध्यान में रखे बिना करते हैं कि पॉलिसी किस शाखा द्वारा जारी की गई थी। अंकीकरण के फलस्वरूप लगभग 28 करोड़ पुरानी पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक आरूप में अंतरित किया जाना संभव होगा।

नयी नियुक्तियां

नयी नियुक्ति

श्री टी.सी.ए. रंगनाथन ने 1 फरवरी, 2010 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (SBBJ) के प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके पूर्व श्री रंगनाथन फरवरी, 2009 से भारतीय स्टेट बैंक, अहमदाबाद सर्किल में मुख्य महा प्रबन्धक के पद पर कार्यरत थे। उन्हें भारतीय स्टेट बैंक के चीन में परिचालन आरंभ करने हेतु सितम्बर, 2005 में उसकी शंघाई शाखा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था।

उत्पाद एवं गठजोड़

आईसीआईसीआई बैंक, यूकेटीआई के बीच गंठजोड़ व्यवस्था

आईसीआईसीआई बैंक और यू के ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट UKTI) ने भारतीय फर्मों की यू. के. में विद्यमान अवसरों से लाभ उठाने में सहायता करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इस संयुक्त पहलकदमी का उद्देश्य यू. के. में विकास करने की उनकी योग्यता बढ़ाने की चाहत रखने वाले भारतीय व्यवसायियों को प्रशिक्षण के अवसर तथा अतिरिक्त आंतरिक निवेश में सहायता प्रदान करना है।

टेलीबैंकिंग सुविधा की शुरूआत

आन्ध्रा बैंक ने हाल ही में काल सेंटर के साथ अपनी टेलीबैंकिंग सुविधा की शुरूआत की है। टेली बैंकिंग प्रणाली 24 X 7 के आधार पर उपलब्ध होने वाली अन्त:- क्रिया ध्वनि प्रत्युत्तर (IVR) प्रणाली के साथ कार्य करती है। उक्त प्रणाली को राष्ट्रीय अवकाशों को छोड कर सप्ताह के सभी दिन प्रशिक्षित काल सेन्टर एजेन्टों के माध्यम से सहायता प्राप्त होती है। हेवलेट पैकर्ड इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक के लिए उसकी कोर बैंकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में ऐस्पेक्ट टेलीबैंकिंग प्रणाली कार्यान्वित की है।

फेडरल बैंक ने बिक्री केन्द्र टर्मिनलों की शुरूआत की

ग्राहकों को प्रौद्योगिकी-चालित सॉल्यूशन उपलब्ध कराने के अपने प्रयासों के तहत फेडरल बैंक ने बिक्री केन्द्र (POS) टर्मिनलों की शुरूआत की है। बैंक ने एक वर्ष के भीतर पूरे देश में एक लाख टर्मिनल स्थापित करने की योजना बना रखी है। व्यापारियों के मामले में मुद्रा के उनके खातों में अंतरित हो जाने के परिणामस्वरूप बिक्री केन्द्र टर्मिनल से किए जाने वाले लेनदेनों से नकदी प्रबन्धन से सम्बन्धित अड़चनें

कम हो जाएंगी। बढ़ी हुई बिक्री के अलावा, व्यापारी गंदे / कटेफटे नोटों को संभालने के जोखिम से भी बच सकते हैं। वर्तमान में ये बिक्री केन्द्र वीसा की स्वीकृति के साथ शुरू किए गए हैं और बैंक शीघ्र ही मास्टर कार्ड, पिन -आधारित कार्डों की स्वीकृति वाले बिक्री केन्द्रों तथा उनमें उपलब्ध होने वाली नकदी आहरण सुविधा और पर्यटन स्थलों पर स्थापित किए जाने के लिए गतिशील मुद्रा परिवर्तन की विशेषता वाले बिक्री केन्द्रों की भी घोषणा करेगा।

पंजाब नैशनल बैंक ने दुबई में परिचालन की शुरूआत की

पंजाब नैशनल बैंक ने दुबई में बैंकिंग परिचालन की शुरूआत कर दी है तथा वह दुबई इंटरनेशनल फाइनैन्सियल सेंटर (DIFC) में एक शाखा की स्थापना करेगा। पंजाब नैशनल बैंक, दुबई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री राज कुमार नायर ने बताया, "दुबई वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अच्छे अवसर उपलब्ध कराता है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे अन्तरराष्ट्रीय कारबार का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बना देती है। हमारी दुबई इंटरनेशनल फाइनैन्सियल सेंटर शाखा सम्पूर्ण मध्य-पूर्व और अफ्रीकी क्षेत्र को लक्ष्यांकित करने के लिए एक आधार का काम करेगी।"

न्यूयार्क के धनलक्ष्मी बैंक ने ऑनलाइन विप्रेषण के लिए गंठजोड़ व्यवस्था की

धनलक्ष्मी बैंक ने अमरीका से भारत को ऑनलाइन विप्रेषण सेवा को सुगम बनाने के लिए बैंक ऑफ न्यूयार्क के साथ भागीदारी व्यवस्था की है। नयी इंटरनेट-आधारित ग्राहक विप्रेषण सेवा सभी, न कि केवल धनलक्ष्मी बैंक के ग्राहकों को अमरीका से भारत को ऑनलाइन निधि अंतरित करने में समर्थ बनाएगी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) / तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (RTGS) के उस मंच, जो भारत में किसी भी स्थान पर स्थित लाभार्थी के बैंक खाते में निधि जमा कर सकता है, का सहारा ले कर भारत को निधि विप्रेषित करने का सुरक्षित एवं सरल तरीका अपना कर उक्त बैंक 24 X7 के आधार पर सेवा प्रदान करते हुए ग्राहक की सुविधा में बढ़ोत्तरी करेगा।

विनियामक के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूरो, येन और पौण्ड-स्टर्लिंग में भावी सौदों की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन और मुद्राओं - यूरो, पौण्ड-स्टर्लिंग और येन में भावी सौदों के लेनदेन की तत्काल प्रभाव से अनुमति दे दी है। यह कदम मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों में डालर - रुपये मे भावी सौदां संविदाओं के क्रय-विक्रय की शुरूआत के डेढ़ वर्ष बाद उठाया गया है। दैनिक रूप से क्रय-विक्रय की जाने वाली मुद्रा वायदा संविदाओं का मूल्य वर्ष 2000 में 60 मिलियन डालर से बढ़ कर 19 जनवरी, 2010 के दिन लगभग 600 मिलियन डालर हो जाने के परिणामस्वरूप बाज़ार के सहभागियों का कहना है कि

लेनदेन के परिमाण से विनियामकों - भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को नये मुद्रा युग्म प्रारंभ करने में सहूलियत हुई होगी। दोनों अग्रणी शेयर बाज़ारों - राष्ट्रीय शेयर बाज़ार और बहु-जिंस बाज़ार- एसएक्स ने नये मुद्रा युग्मों में शीघ्र ही लेनदेन आरंभ करने की योजना बना रखी है।

अस्थिर पूंजी प्रवाहों से समस्याएं पैदा हो सकती हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर श्रीमती श्यामला गोपीनाथ को भय है कि त्वरित एवं अस्थिर पूंजी अन्तर्वाहों अथवा बहिर्वाहों से महत्वपूर्ण नीतिगत चुनौतियां उठ खड़ी हो सकती हैं, जिनका परिणाम संभाव्य रूप से विनिमय दर में अतिलंघन, परिसम्पत्ति की कीमत में अस्थिरता और वित्तीय अस्थिरता के रूप में सामने आ सकता है। उन्होंने कहा कि "इस संदर्भ में उभरते बाज़ारों द्वारा वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए पूंजीगत खाते के विनियमनों के समुचित एवं व्यावहारिक उपयोग पर विचार किया जाना होगा।" श्रीमती गोपीनाथ ने कहा कि हालांकि, इस समय पूंजी अन्तर्वाह चिंता का विषय नहीं है। "हम (रुपये के) स्तरों पर नहीं केवल अस्थिरता पर ध्यान देते हैं। अन्तर्वाहों के सम्बन्ध में कोई चिंता नहीं है।"

ऋण व्यतिक्रमों की अदला-बदली (swaps) विचाराधीन : भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर श्रीमती श्यामला गोपीनाथ ने कहा है कि ऋण व्यतिक्रम की अदला-बदली (swaps) की शुरूआत पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। "हम मुद्रा वायदों के लिए अन्य मुद्रा युग्मों की शुरूआत करने के मुद्दे पर काफी आगे पहुंच चुके हैं तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के परामर्श से प्लेन वनीला मुद्रा विकल्प की अनुमति देने के मुद्दे की जांच कर रहे हैं।" कॉरपोरेट बॉण्डों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि कॉरपोरेट बॉण्डों मे पुन: खरीद (Repo) के सम्बन्ध में दिशानिर्देशों के मसौदे पर प्रति-सूचना प्राप्त हो चुकी है, जो व्यापक रूप से सकारात्मक है, किन्तु उठाया गया मुख्य मुद्दा जमा प्रमाण पत्रों (CDs) / वाणिज्यिक पत्रों (CPs) जैसे अल्पावधिक मुद्रा बाज़ार लिखतों के पुन: खरीद (Repo) के लिए पात्र प्रतिभूतियों के रूप में समावेश से सम्बन्धित है। "प्रारंभ में केवल उच्चतर श्रेणी-निर्धारित बॉण्डों से शूरूआत किए जाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में अंतिम दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।"

सेबी ने प्रतिभूतियां उधार लेने से सम्बन्धित नियम आशोधित किए

बाज़ार विनियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने प्रतिभूतियां उधार देने और उधार लेने (SLB) से सम्बन्धित ढांचे को बाज़ार के सहभागियों से प्राप्त प्रति-सूचना के अनुसार आशोधित कर दिया है। इस कार्रवाई से प्रतिभूतियां उधार देने और उधार लेने की प्रणाली में सुधार होगा और बेहतर कीमत अन्वेषण में सुविधा होगी, क्योंकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने वर्तमान 30 दिन से अधिक की

सीमा के स्थान पर अधिकतम 12 महीनों वाली प्रतिभूतियों की शर्त पर प्रतिभूतियां उधार देने और उधार लेने की अनुमति प्रदान की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को खुदरा बॉण्ड निर्गमों के सम्बन्ध में चेतावनी दी

भारतीय स्टेट बैंक के खुदरा निवेशकों के लिए प्रस्तावित बॉण्ड निर्गम के पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अस्थिर दर वाले लिखतों को मीयादी जमा की दरों से असम्बद्ध रखा जाए। इसके अलावा, विनियामक ने बैंकों के लिए एक चेतावनी का जारी किया जाना भी अनिवार्य कर दिया है और यहां तक कि प्रस्ताव-प्रलेख तथा आवेदन पत्र में शामिल की जाने वाली उस चेतावनी की वाक्य-रचना और फोन्ट के आकार का विनिर्देशन भी कर दिया है। इसके अतिरिक्त वह चाहता है कि ऐसे बैंक जिन्होंने गौण ऋण के माध्यम से टियर II पूंजी जुटाई है, यह सुनिश्चित करें कि मीयादी जमा और बॉण्ड के बीच विद्यमान अंतर को स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है। टियर II पूंजी का निर्धारण किसी बैंक के समग्र पूंजी आधार के एक अंग के रूप में किया जाता है तथा उसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना करने में शामिल किया जाता है। इसके विपरीत, जमाराशियां ऐसी देयताएं होती हैं, जिनसे बैंक की शक्ति का संकेत नहीं प्राप्त होता। 1 लाख रुपये तक की खुदरा जमाराशियां बीमा सुरक्षा के साथ प्राप्त होती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि विनियामक पूंजी लिखतों की जोखिम विशेषताओं के सम्बन्ध में निवेशक शिक्षण को बढ़ाने के लिए एहतियात महत्वपूर्ण होते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से बीमा बिक्री से प्राप्त राशियों को प्रकट करने के लिए कहा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से उनके द्वारा अपने खाता धारकों को की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की विक्रियों के माध्यम से अर्जित शुल्कों एवं कमीशनों के प्रकार को प्रकटित करने के लिए कहा है। इससे आईसीआईसीआई बैंक, एचएफडीसी बैंक, ऐक्सिस बैंक, एचएसबीसी, सिटीबैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (जिन्होंने एक साथ मिला देने पर लगभग 1,000 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं) जैसे घरेलू, निजी बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित कमीशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक ने भी उसकी सहायक कम्पनी एसबीआई लाइफ के प्रीमियम, जो बैंक द्वारा बेची गई पॉलिसियों से उद्भूत होता है, के माध्यम से उल्लेखनीय स्तर का कमीशन अर्जित किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा अगस्त, 2009 से पारस्परिक निधियों को भार-रहित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप बैंक बीमा पॉलिसियों द्वारा कमीशन आय में वृद्धि किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोखिमों के न्यून मूल्य-निर्धारण के विरुद्ध चेतावनी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर श्रीमती उषा थोरात द्वारा किए गए उल्लेख के अनुसार प्रणाली में अतिरिक्त चलनिधि की मौजूदगी के कारण बैंक एक बार पुन: उप-मूल उधार दर पर अल्पावधिक उधार देने का मार्ग अपना रहे हैं। श्रीमती थोरात ने अभिमत व्यक्त किया है कि जोखिम का मूल्य-निर्धारण करना

महत्वपूर्ण है। जब कभी चलनिधि की अधिकता हो जाती है और लाभ अर्जित करने का दबाव बढ़ता है, जोखिम के न्यून मूल्य-निर्धारण के प्रति प्रलोभन की प्रवृत्ति बन जाती है। लागत से कम स्तर पर मूल्य-निर्धारण जोखिमपूर्ण हो सकता है तथा जोखिम लागत अक्सर पर्याप्त रूप से कैप्चर नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त, इससे परिसम्पत्ति की कीमतों में कृत्रिम वृद्धि हो जाती है। श्रीमती थोरात ने बैंकों द्वारा ऋण-उन्मुख पारस्परिक निधियों में भारी मात्रा में निवेश किए जाने के प्रति भी आगाह किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक विशेष ऋण दरों के बारे में चिंतित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विशेष ऋण दरों पर चिंता व्यक्त की है। भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर श्रीमती उषा थोरात को लगता है कि इस चिंता का कारण बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही 'टीज़र दर' है, इस प्रकार उन्होंने विशेषत: उस स्थिति में जब अशोध्य ऋण दि-ब-दिन बढ़ रहे हों, ऐसे प्रस्तावों से भारतीय रिज़र्व बैंक को होने वाली असुविधा का संकेत कर दिया है। ग्राहकों को आकर्षित करने के अभियान में कुछेक बैंक गृह ऋण पहले दो वर्षों के लिए एक विशेष अथवा स्थिर दर पर उपलब्ध करा रहे हैं और उसके बाद वे उसे अस्थिर दर के आधार पर परिवर्तित कर लेते हैं। इस प्रकार की टीजर दरें एक विनिर्दिष्ट अवधि तक एक नियत अपेक्षाकृत कम प्रारंभिक ब्याज दर की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। ब्याज दरों में जब कभी वृद्धि होनी प्रारंभ होती है, अस्थिर दर के बढ़ जाने की आशा की जाती है। श्रीमती थोरात ने कहा है, "मुझे आशा है कि टीजर दरों के इस परिदृश्य में बैंक यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उधारकर्ता इस प्रकार की दरों के निहितार्थों से अवगत हों तथा मूल्यांकन में इन दरों के सामान्य हो जाने पर उधारकर्ताओं की चुकौती क्षमता को ध्यान में रखा जाता है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों को कठिन समय के लिए सुरक्षित भण्डार बनाने के लिए निदेश देगा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को इस आशय के निदेश देने का मन बना लिया है कि वे लाभांश दे कर अपने लाभों को खंडित न करें, अपितु इसके बजाय उन निधियों का उपयोग ऐसी पूंजी निर्मित करने में करें, जो कठिन दौर में उनकी चलनिधि समस्याओं को दूर करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य महा प्रबन्धक श्री बी. महापात्र ने कहा है कि हाल के संकट ने भारतीय बैंकों के लिए किसी प्रकार की शोधक्षमता की समस्या नहीं निर्मित की, किन्तु चलनिधि समस्याएं मौजूद थीं, जिनके परिणामस्वरूप शोधक्षमता के मुद्दे उठ खड़े हुए। भारतीय रिज़र्व बैंक चलनिधि से सम्बन्धित विनियमनों की व्यवस्था करने की योजना बना रहा है, ताकि बैंक मुद्रा बाज़ार से निधियों के स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय चलनिधि का प्रबन्धन अपने आप ही कर सकें। भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी बारी वाला एक ऐसा सुरक्षित भण्डार निर्मित करने पर विचार कर रहा है, जिसके तहत बैंकों को उस अवधि में अपने लाभों को लाभांशों के रूप में खंडित करने के बजाय अच्छे समय के दौरान पूंजी एकत्रित करने की अनुमति दी जा सकती है। श्री महापात्र ने यह सूचित किया कि अल्पावधिक पूंजी पर्याप्तता प्रणाली में भारी परिवर्तन किया जाएगा और कारबार करने के लिए बैंकों से संभवत: और अधिक पूंजी अपेक्षित होगी तथा उनके लिए अपेक्षाकृत अधिक जोखिम सुरक्षा निर्धारित की जाएगी।

इर्डा ने प्रकटन दिशानिर्देश जारी किए

बीमा कम्पनियों के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) से सम्बन्धित दिशानिर्देशों की ओर एक कदम बढ़ाने के रूप में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने मार्च 2010 से प्रभावी होने वाले अंतिम सार्वजनिक प्रकटन से सम्बन्धित मानदंड जारी कर दिया है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कहा है, "कतिपय बीमा कम्पनियां शीघ्र ही 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेंगी तथा विनियामक द्वारा उन्हें प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव जारी करने की अनुमति दी जा सकती है। यह आवश्यक है कि निवेशक बीमा कम्पनियों की वित्तीय कार्य-निष्पादन प्रोफाइल, वित्तीय स्थिति, जोखिम अनाश्रयता (exposure) एवं प्रबन्धन से पूरी तरह अवगत हों। इनसे सम्बन्धित अधिमानत: कम से कम पांच वर्ष के आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे।"

विशिष्ट घटनाएं

बैंक रहित पंचायतों में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं

बैंकिंग सेवाएं पश्चिम बंगाल के जिलों में स्थित लोगों तक पहुंचाने तथा बैंक-रहित ग्राम पंचायतों (GP) को बैंकिंग सुविधा के तहत लाने के उद्देश्य से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने मुर्शिदाबाद जिले में पलसंदा, हरोरा और मालंचा में शाखाएं खोली हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री टी.एम. भसीन ने कहा, "पलसंदा और मालंचा मे इन दो शाखाओं के खुल जाने के साथ ही हम बैंक-रहित ग्राम पंचायतों में पांच शाखाएं खोल चुके हैं और इस वित्त वर्ष की समाप्ति तक छ: और शाखाएं खोलने के बारे में आशान्वित हैं।"

जीएमएटी प्रकार का मॉडल बैंकों की पसंद

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नौकरी पाने के आकांक्षी युवकों को शीघ्र ही जीएमएटी जैसे अर्हक अंक की आवश्यकता पड़ सकती है। बैंकिंग उद्योग इस समय विद्यमान परंपरा, जिसमें अलग-अलग बैंक अपने कार्मिकों की भर्ती सीधे ही कर लेते हैं, के विपरीत कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए सामान्य (साझी) प्रवेश परीक्षा की योजना बना रहा है। भारतीय बैंक संघ (IBA) ने हाल ही में देश के वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षा का प्रस्ताव रखा था। इस विचार का बैंकों और उनके साथ ही साथ बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS), जो अधिकांश बैंकों के लिए चयन प्रक्रिया का प्रबन्धन करता है, द्वारा समर्थन किया गया। उक्त प्रस्ताव के अनुसार कोई बैंक सफल अभ्यर्थियों के उस समूह से कार्मिकों की भर्ती करने में समर्थ होगा, जो भारतीय बैंक संघ निर्मित करेगा।

भारतीय स्टेट बैंक कम लागत वाले हैंडसेटों से भी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगा

भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबन्ध निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) श्री ए. कृष्ण कुमार के अनुसार तीव्र गति से बढ़ रहे मोबाइल फोन ग्राहक आधार की जरूरतें पूरी करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक एक ऐसी प्रौद्योगिकी अपनाने की दिशा में कार्यरत है, जो ग्राहकों को कम लागत वाले मोबाइल हैंडसेटों से भी मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करने में समर्थ बनाएगी। श्री कुमार ने बताया, "हम मुंबई स्थित स्पैंकों टेली सिस्टम के साथ मिल कर अपने ग्राहकों के कम लागत वाले हैंडसेटों में सॉफ्टवेयर का विन्यास करने और उसे ग्राहकोनुकूल बनाने की दिशा में कार्यरत हैं।" वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक इस सेवा का उपयोग केवल विशिष्ट प्रकार के अधिक लागत वाले हैंडसेटों के ही माध्यम से कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी मोबाइल बैंकिंग सेवा की शुरूआत वर्ष 2008 में स्पैंको टेली सिस्टम की भागीदारी में की थी।

निष्क्रिय बैंक खातों को नष्ट करना मिथ्याचारी प्रथा

दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने किसी खाते के लम्बी अवधि तक निष्क्रिय रहने पर किसी बैंक द्वारा उसे नष्ट किए जाने की प्रथा की निंदा की है। आयोग ने यह आदेश खाता धारक के खाते को पुन: खोले जाने के अलावा उसे भुगतान किए जाने के मंच के निर्देश को चुनौती देते हुए एक बैंक की याचिका पर दिया है। आयोग ने कहा है, "बैंकों को किसी ऐसे खाते से, जो 8 वर्षों से परिचालित न किया गया हो, सम्बन्धित कागजात जलाने की अनुमति दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण होगा।"

इंडियन ओवरसीज़ बैंक ग्रामीण अभियान के लिए सेल फोन कम्पनियों के एजेन्टों का सहयोग लेगा

इंडियन ओवरसीज़ बैंक (IOB) के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एस.ए. भट्ट द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की पहुंच बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में उनके एजेन्टों का उपयोग कारबार संपर्कियों (BCs) के रूप में करने हेतु इंडियन ओवरसीज़ बैंक मोबाइल फोन सेवा प्रदाताओं के साथ वार्तालाप कर रहा है। चूंकि अधिकांश मोबाइल फोन सेवा प्रदाताओं ने उनके सिम कार्डों को बेचने के लिए एजेन्टों को नियुक्त कर रखा है, वही एजेन्ट कारबार संपर्कियों का भी कार्य कर सकते हैं। चेन्नई-स्थित बैंक अपने ग्रामीण कारबार पर संकेन्द्रण के एक अंग के रूप में इस वित्त वर्ष की समाप्ति तक अपने कारबार संपर्कियों की संख्या भी 100 से बढ़ा कर 300 कर रहा है। बैंक मार्च तक शहरी क्षेत्र में और उसके साथ ही कस्बाई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 53 नयी शाखाएं भी खोलेगा। इस विस्तार कार्यक्रम को सहायता प्रदान करने हेतु भर्ती की मात्रा को अंतिम रूप देने का कार्य भी जारी है।

नेट पर बैंकिंग समझदारी का प्रतीक है

वर्ष 2008 में साइबर अपराध की घटनाओं से जुड़ी इंटरनेट धोखाधडियों में में देश भर के बैंकों ने 6.57 करोड़ रुपये की रकम गंवाई थी, जिसमें तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। हालांकि, इससे लोगों को

ऑनलाइन बैंकिंग, जिससे असंख्य लाभ होते हैं, का उपयोग करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। यह ग्राहक को उसके बिजली, टेलीफोन, गैस और अन्य बिलों का तत्काल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है। ग्राहक बैंक को आवर्ती बिलों का स्वयमेव भुगतान करने का स्थायी अनुदेश भी दे सकता है, यह सब प्रत्येक बिल आहर्ता को एक बार वाला एक पंक्ति का सामान्य अनुदेश दे कर किया जा सकता है। सुविधाजनक होने के अलावा यह नि:शुल्क सेवा भी है। ग्राहक दिन के किसी समय और जितनी चाहे उतनी बार लेनदेनों की जांच कर सकता है।

आस्ट्रेलियाई बैंक भारत में शाखा खोलेगा

आस्ट्रेलिया की अग्रणी वित्तीय संस्था कॉमनवेल्थ बैंक वर्ष 2010 की दूसरी तिमाही में भारत (मुंबई) मे अपनी पहली शाखा खोलेगा। कॉमनवेल्थ बैंक के वाणिज्यिक बैंकिंग प्रभाग के प्रधान श्री प्रवीण बत्रा ने बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसी शाखा खोलने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जो भारत, आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बीच व्यापार के वित्तीयन पर ध्यान केन्द्रित करेगी। इसके पूर्व उक्त बैंक ने बेंगलूर में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोल रखा था।

बैंकों के तीसरी तिमाही के परिणाम

करोड़ रुपयों में

बैंक	ब्याजगत आय	परिवर्तन %	अन्य आय	परिवर्तन %	निवल लाभ	परिवर्तन %
एचडीएफसी बैंक	4034.81	-9.70	853.01	-9.19	818.50	31.60
ऐक्सिस बैंक	2883.65	-3.30	988.09	34.90	655.98	30.90
इंडसइंड बैंक	702.92	12.00	116.02	-12.81	88.04	95.38
आईडीबीआई बैंक	4007.80	23.93	425.59	52.56	287.15	28.98
केनरा बैंक	4687.81	1.35	781.29	3.15	1052.58	50.05
बैंक ऑफ इंडिया	4486.23	3.29	571.60	-45.59	405.50	-53.51
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3131.30	15.03	364.12	17.01	308.44	-13.25
ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2671.59	11.29	237.68	-25.19	289.43	14.77
इंडियन ओवरसीज़ बैंक	2570.14	-1.09	258.52	-57.38	101.70	-73.82
देना बैंक	1015.90	6.31	133.14	-3.47	134.52	-4.16
फेडरल बैंक	944.84	7.81	116.48	-29.32	110.25	-45.93

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

आस्ति एवं देयता प्रबन्धन : बैंक के शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक सम्पत्ति को अधिकतम करने हेतु बैंक की आस्तियों एवं देयताओं का प्रबन्धन। इसके लिए चलनिधि की आवश्यकताएं पूरी करने, चूक के अतिशय जोखिम से बचने हेतु आयोजना बनाने, ब्याज दर जोखिम के प्रति अवांछित अनाश्रयता (एक्सपोजर) से बचने के लिए परिपक्वताओं एवं अवधियों की योजना तैयार करने और निधियों की लागत और उनसे होने वाले प्रतिलाभों के बीच पर्याप्त अंतर सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित और प्रदत्त ब्याज दरों को नियंत्रित रखने की आवश्यकता होती है। प्रबन्धन निवल आय और/ अथवा बदलती ब्याज दरों की तुलना में शेयरधारकों की इक्विटी के आर्थिक मूल्य की संवेदनशीलता का पता लगाने पर ध्यान केन्द्रित रखता है।

शब्दावली

प्रावधान के मानदंड

यह मानते हुए कि ऋण का एक निश्चित प्रतिशत अशोध्य हो जाएगा, बैंक उनके लाभ के एक हिस्से को इस प्रकार की हानियों को सुरक्षित रखने के लिए अलग रख देते हैं। यह रकम कर-पूर्व आय से घटा दी जाती है तथा अशोध्य हो चुकी उधार दी गई राशि के लिए एक समयोपयोगी निधि (cushion) सृजित करने हेतु अलग रख दी जाती है। सामान्य प्रावधानीकरण से आशय है वह प्रावधानीकरण जो बैंकों को उनके द्वारा दिए जाने वाले सभी अग्रिमों के लिए करना होता है, जबकि विशिष्ट प्रावधानीकरण से अभिप्राय है स्थावर संपदा या पूंजी बाज़ारों जैसी विशिष्ट श्रेणियों को दिए गए उधारों के लिए किए जाने वाले प्रावधान। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट नये मानदंडों में यह अपेक्षित है कि सभी बैंक सितम्बर, 2010 तक 70 % की सामान्य प्रावधान सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त कर लें।

प्रतिभूतिया उधार देना और उधार लेना

प्रतिभूतिया उधार देने और उधार लेने के कारबार से निवेशक निष्क्रिय पड़ी प्रतिभूतियों को समाशोधन निगम को उधार देने और तथा उसके माध्यम से प्रतिलाभ अर्जित करने में समर्थ होते हैं। प्रतिभूतियां उधार देने और लेने की प्रणाली के लिए शेयर बाज़ार का समाशोधन निगम नोडल एजेन्सी होगा तथा वह अनुमोदित मध्यवर्ती (Intermedidiaries) के रूप में पंजीकृत होगा। समाशोधन निगम सदस्यों की ओर से कमियों को पूरा करने के प्रयोजन हेतु प्रतिभूतियां उधार ले सकता है। चूककर्ता बिक्री दलाल सुपुर्दगी समाशोधन निगम द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करेगा। चूककर्ता बिक्री दलाल के विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सुपुर्दगी करने में असफल हो जाने की स्थिति में समाशोधन निगम को प्रतिभूतियों को खुले बाज़ार

से खरीदना होगा तथा उसे उधारदाता को सात व्यापार दिवसों के भीतर वापस करना होगा। बाज़ार से प्रतिभूतियां खरीदने में असमर्थता की स्थिति में लेनदेन समाप्त कर दिया जाएगा।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत

- पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
  पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या 15 / दक्षिण / 2010 -12

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 26वीं तारीख को प्रेषित करें।

संस्थान समाचार

कारबार संपर्कियों / कारबार सुसाधकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने कारबार संपर्कियों / कारबार सुसाधकों के लिए अपने प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हेतु पंजाब नैशनल बैंक के लिए 11 से 12 जनवरी 2010 के बीच में नयी दिल्ली में तथा धन फाउंडेशन के लिए 21 से 22 जनवरी, 2010 के बीच मदुराई में दो "प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम" (TTP) आयोजित किए।

सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान 29 जनवरी 2010 को आयोजित हुआ

"विनिवेश एवं निजीकरण से सम्बन्धित रणनीतियां" विषय पर 26वां सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान डॉ. विजय केलकर, अध्यक्ष वित्त आयोग द्वारा 29 जनवरी 2010 को भारतीय स्टेट बैंक सभागृह, मुंबई में दिया गया। उक्त व्याख्यान संस्थान की वेबसाइट www.iibf.org.in पर उपलब्ध है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स के पास उनकी ई-मेल आईडी को नीचे वर्णित फार्म के अनुसार अद्यतन करा लें तथा उसे निम्नलिखित को प्रेषित करें :

उप निदेशक (सदस्यता)
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, दि आर्केड, टॉवर 4, 2री मंजिल, कफ परेड, मुंबई - 400005 अथवा iibgen@bom5.vsnl.net.in पर ई-मेल कर दें।

नाम :---------- सदस्यता संख्या :----------

ई-मेल आईडी :----------आवेदित परीक्षा : ----------

बाज़ार की खबरें

बाज़ार का आशुचित्र (रकम मिलियन रुपयों में)					
संकेतक	01जनवरी 2010	08 जनवरी 2010	15 जनवरी 2010	22जनवरी 2010	29 जनवरी 2010
मुद्रास्फीति (%)	4.78 % (दिसम्बर 2009)	4.78 % (दिसम्बर 2009)	7.31 % (दिसम्बर 2009)	7.31 % (दिसम्बर 2009)	7.31 % (दिसम्बर 2009)
औसत चलनिधि समायोजन सुविधा प्रत्यावर्ती पुन: खरीद परिमाण	6,15,,888	9,50,980	7,45,990	7.44,480	7,60.388
औसत चलनिधि समायोजन सुविधा पुन: खरीद दरें (%)	2750	0	0	0	750
औसत पुन: खरीद दरें	2.61	3.06	2.87	2.94	2.89
10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति का प्रतिफल (%	7.6539	7.7278	7.7037	7.6168	7.6687
1-10 वर्ष का अंतर (आधार अंक)	284	302	304	300	303
6 माह का वायदा प्रीमियम (%)	2,92	2.54	2.93	2.79	2.97
6 माह का अमरीकी डालर लिबोर (%)	0.43	0.42	0.40	0.39	0.39

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) के न्यूज़लेटर्स, जनवरी, 2010

भारित औसत मांग दरें

3.50
3.40
3.30
3.20
3.10

3.00
2.90
2.80
2.70
2.60
2.50

01/01/10 02/01/10 04/01/10 05/01/10 06/01/10 07/01/10 08/01/10 09/01/10
11/01/10 12/01/10 13/01/10 14/01/10 15/01/10 16/01/10 118/01/10 19/01/10
20/01/10 21/01/10 22/01/10 23/01/10 25/01/10 27/01/10 28/01/10 29/01/10

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर्स, जनवरी 2010

विनिमय दर
अमरीकी डालर / भारतीय रुपया नियत एवं अंतिम

46.80
46.60
46.40
46.20
45.80
45.60
45.40
45.20
45.00

पूर्वान्ह 11.30 बजे
अपरान्ह 5.00 बजे

01-01-10	15-01-10	29-01-10

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

श्री आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, श्री आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, 'दि आर्केड', विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूव स्कंध, कफ परेड, मुंबई - 400 005 से प्रकाशित।

संपादक : श्री आर. भास्करन

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
दि आर्केड, विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व खण्ड, कफ परेड,
मुंबई - 400 005

टेलीफोन : 2218 7003 /

आईआईबीएफ विज़न फरवरी, 2010